

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:—दिनांक 15.07.2017 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व अन्य समाचार पत्रों में राजकीय नारी निकेतन में निवासरत संवासिनियों के छायाचित्र प्रकाशित किये जाने पर कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 15.07.2017 (छायाप्रति संलग्न) को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के "अपना शहर देहरादून" में "नारी निकेतन हंगामे के बाद हरकत में सरकार और प्रशासन" खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) पीड़ित संवासिनियों का फोटो छापा गया है तथा उसी तिथि दिनांक 15.07.2017 (छायाप्रति संलग्न) के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में "मंत्री के सामने फफ्फू पड़ी संवासिनियां" खबर के साथ ही मानसिक रूप से विक्षिप्त संवासिनी की फोटो व दो पोक्सो पीड़ित का वास्तविक नाम का उल्लेख किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.07.2017 को राजकीय नारी निकेतन में मीडिया का प्रवेश कैसे व किसी की अनुमति से हुआ, किन्सा के द्वारा संवासिनियों का फोटो खींचा गया आदि के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये राजकीय नारी निकेतन की प्रवेश पंजिका व प्रश्नगत दिन की सी.सी.टी.वी. फुटेज की प्रति भी तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय नारी निकेतन में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस/मीडिया का प्रवेश वर्जित है तथा किसी भी संवासिनी का फोटो खींचना व उसको प्रकाशित करना पूर्णतः वर्जित है। यदि किसी महिला या बालिका की पहचान या परिजन की तलाश हेतु उनकी फोटो अखबार में दिया जाना हो तो क्रमशः जिला प्रोबेशन अधिकारी/बाल कल्याण समिति की अनुमति से ही किया जाय। इसके लिये फोटो जिला प्रोबेशन अधिकारी/बाल कल्याण समिति द्वारा ही खींचा जा सकता है। किसी प्रकार के आयोजनों/कार्यक्रमों की फोटो जिला प्रोबेशन अधिकारी/बाल कल्याण समिति की